

भारत में स्कूली छात्रों पर COVID-19 महामारी और लॉकडाउन का प्रभाव: मध्य प्रदेश के छात्रों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव के विशेष संदर्भ में एक समीक्षा

राम सिंह यादव

शोधार्थी

सारांश

COVID-19 महामारी, जो 2019 के आखिर में शुरू हुई और 2020-2021 के दौरान पूरी दुनिया में फैल गई, उसने दुनिया भर के शिक्षा सिस्टम में पहले कभी न देखी गई रुकावट पैदा कर दी। भारत में, मार्च 2020 और 2021 के बीच लागू किए गए लगातार देशव्यापी और राज्य-स्तरीय लॉकडाउन की वजह से लगभग 15 लाख स्कूल बंद हो गए, जिससे 24 करोड़ 70 लाख से ज्यादा स्कूली बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा। मध्य प्रदेश, जो भारत के उन राज्यों में से एक है जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में पहले से ही कई चुनौतियाँ मौजूद हैं, वहाँ इस महामारी का असर और भी ज्यादा गंभीर रहा। इसकी मुख्य वजहें थीं—डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले से मौजूद कमियाँ, गरीबी की उँची दरें, और सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों से आने वाले छात्रों की बड़ी संख्या। नतीजतन, मध्य प्रदेश के कई छात्रों को दूरस्थ शिक्षा (रिमोट लर्निंग) के मौकों तक पहुँचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और वे अपनी पढ़ाई में पीछे रह गए।

उचित संसाधनों और सहयोग की कमी ने राज्य में पहले से मौजूद शैक्षिक असमानताओं को और बढ़ा दिया, जिससे सुविधा-संपन्न और सुविधा-वंचित छात्रों के बीच का अंतर और चौड़ा हो गया। सरकार और गैर-लाभकारी संगठनों ने मिलकर राहत उपाय प्रदान करने और सबसे अधिक संवेदनशील आबादी तक शिक्षा की पहुँच को बेहतर बनाने के लिए काम किया, लेकिन मध्य प्रदेश की शिक्षा प्रणाली पर महामारी के दीर्घकालिक प्रभाव अभी भी अनिश्चित हैं। यह समीक्षा पत्र भारत में स्कूली छात्रों पर COVID-19 और महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के बहुआयामी प्रभावों की व्यवस्थित रूप से जाँच करता है, जिसमें मध्य प्रदेश का विशेष संदर्भ दिया गया है। माध्यमिक डेटा, सरकारी रिपोर्टें, पीयर-रिव्यूड साहित्य और पहले प्रकाशित शिक्षा सर्वेक्षणों के आधार पर, यह अध्ययन पाँच प्रमुख क्षेत्रों में प्रभावों का विश्लेषण करता है: (1) सीखने में कमी और शैक्षणिक पिछड़ापन, (2) मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले परिणाम, (3) डिजिटल विभाजन और ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियाँ, (4) स्कूल छोड़ने की दरें और बाल श्रम तथा कम उम्र में विवाह के प्रति संवेदनशीलता, और (5) मध्याह्न भोजन योजना के निलंबन के कारण पोषण की कमी। समीक्षा से पता चलता है कि महामारी ने मौजूदा शैक्षणिक असमानताओं को और गहरा कर दिया है, जिसका असमान बोझ पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों, लड़कियों, आदिवासी (अनुसूचित जनजाति) छात्रों और ग्रामीण छात्रों को उठाना पड़ रहा है। यह शोध-पत्र नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए साक्ष्य-आधारित सिफारिशों के साथ समाप्त होता है, जिनका उद्देश्य मध्य प्रदेश और समग्र रूप से भारत में शिक्षा प्रणाली की न्यायसंगत बहाली को संभव बनाना है।

1. परिचय

11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किए गए COVID-19 के प्रकोप ने एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक संकट पैदा कर दिया। दुनिया भर की सरकारों ने इसे रोकने के मुख्य उपायों के तौर पर लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों और सार्वजनिक जगहों को बंद करने का सहारा लिया। इन उपायों का शिक्षा क्षेत्र पर गहरा असर पड़ा, जिससे स्कूलों और विश्वविद्यालयों को बंद करना पड़ा और उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई की ओर मुड़ना पड़ा। इस अचानक आए बदलाव ने छात्रों के बीच टेक्नोलॉजी और इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुँच में पहले से मौजूद असमानताओं को उजागर किया, जिससे शैक्षिक विभाजन और भी चौड़ी हो गई। जैसे-जैसे स्कूल धीरे-धीरे फिर से खुल रहे हैं और छात्र कक्षाओं में लौट रहे हैं, मध्य प्रदेश के शिक्षकों और नीति निर्माताओं को इन चुनौतियों का समाधान करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महामारी के बाद की दुनिया

में सभी छात्रों को सीखने और सफल होने के समान अवसर मिलें। सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक शिक्षा क्षेत्र था। UNESCO के अनुसार, अप्रैल 2020 में महामारी के चरम पर, 190 से ज़्यादा देशों में 1.6 अरब से ज़्यादा छात्र स्कूल से बाहर थे; यह इतिहास में शिक्षा में अब तक की सबसे बड़ी एक साथ आई रुकावट थी।

भारत में, केंद्र सरकार ने 24 मार्च, 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की। इसके सीधे नतीजे के तौर पर, देश भर के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया गया। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा (डिस्टेंस लर्निंग) के तरीकों को अपनाने का निर्देश दिया। हालाँकि, भारत की शिक्षा प्रणाली में मौजूद ढाँचागत असमानताओं - विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच भारी डिजिटल विभाजन, सामाजिक-आर्थिक विषमताओं और बुनियादी ढाँचे की कमी - ने इस बदलाव को बेहद असमान बना दिया। ग्रामीण इलाकों के कई छात्रों के पास भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक पहुँच नहीं थी, जिससे उनके लिए ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होना लगभग असंभव हो गया। इसके अलावा, आर्थिक तंगी का सामना कर रहे परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई दूर से जारी रखने के लिए ज़रूरी तकनीक का खर्च उठाने में असमर्थ थे। नतीजतन, कई छात्र अपनी पढ़ाई में पिछड़ गए, जिससे पहले से मौजूद उपलब्धि के अंतर (achievement gap) में और बढ़ोतरी हुई। नीति निर्माताओं के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि वे इन असमानताओं को दूर करें और ऐसे समाधान लागू करें जो यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में सभी छात्रों के पास अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए ज़रूरी संसाधन उपलब्ध हों।

इस संदर्भ में मध्य प्रदेश (MP) का स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लगभग 72.6 मिलियन (जनगणना 2011) की आबादी और 69.3% साक्षरता दर के साथ, इस राज्य को ऐतिहासिक रूप से शैक्षिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। MP में अनुसूचित जनजाति (ST) और अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों का अनुपात काफी अधिक है; यहाँ की अधिकांश आबादी ग्रामीण है और गरीबी की दर भी उँची है। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का 'सकल नामांकन अनुपात' (GER) महामारी से पहले भी राष्ट्रीय औसत से नीचे था, और इसके स्कूली बुनियादी ढाँचे के संकेतक अधिक विकसित राज्यों की तुलना में पीछे थे। इन कारकों के कारण मध्य प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच शैक्षिक अंतर और भी बढ़ गया है। स्कूलों में पर्याप्त संसाधनों, योग्य शिक्षकों और बुनियादी ढाँचे की कमी ने सभी छात्रों के लिए शैक्षिक परिणामों को बेहतर बनाने के राज्य के प्रयासों में बाधा डाली है। परिणामस्वरूप, इन असमानताओं को दूर करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच को बेहतर बनाने की पहल अब MP के नीति-निर्माताओं के लिए एक प्राथमिकता बन गई है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, नामांकन दरों में वृद्धि और वंचित समुदायों पर विशेष ध्यान केंद्रित करके, राज्य का लक्ष्य इस अंतर को पाटना और मध्य प्रदेश के सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना है।

इस समीक्षा पत्र का उद्देश्य COVID-19 महामारी और लॉकडाउन के स्कूल जाने वाले छात्रों पर पड़े बहुआयामी प्रभावों से जुड़े मौजूदा साक्ष्यों को एक साथ लाना है, जिसमें मध्य प्रदेश पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह पत्र 2020-2021 की अवधि की सरकारी रिपोर्टों, शिक्षा सर्वेक्षणों, प्रकाशित अकादमिक लेखों और विश्लेषणों पर आधारित है, ताकि इस बात की एक विस्तृत तस्वीर पेश की जा सके कि किस तरह इस महामारी ने लाखों युवा शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा के परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया।

2. पृष्ठभूमि और संदर्भ

2.1 भारत में स्कूली शिक्षा की महामारी-पूर्व स्थिति

COVID-19 के आने से पहले, भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था की पहचान उसकी बड़ी उपलब्धियों के साथ-साथ लगातार बनी रहने वाली ढाँचागत चुनौतियों से होती थी। शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009, नामांकन दरों को बेहतर बनाने में काफी हद तक सफल रहा था, और पूरे देश में प्राथमिक स्कूलों में लगभग सभी बच्चों का नामांकन दर्ज किया गया था। 'एनुअल स्टेटस ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट' (ASER) 2019 में यह बात सामने आई कि सरकारी स्कूलों में नामांकन की स्थिति स्थिर हो गई थी, फिर भी सीखने के परिणाम एक गंभीर चिंता का विषय बने हुए थे—कक्षा 5 के छात्रों का एक बड़ा हिस्सा कक्षा 2 के स्तर का पाठ भी नहीं पढ़ पाता था।

'मध्याह्न भोजन योजना' (Mid-day Meal Scheme) आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले लाखों छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच का काम करती थी; इसने कुपोषण की समस्या को दूर करने में मदद की और साथ ही स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में भी काम किया। मध्य प्रदेश (MP) में, महामारी से पहले, इस योजना के तहत सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के 70 लाख से भी अधिक छात्रों को शामिल किया गया था।

2.2 मध्य प्रदेश की महामारी-पूर्व शैक्षिक प्रोफ़ाइल

महामारी से पहले मध्य प्रदेश के शैक्षिक संकेतक एक मिली-जुली तस्वीर पेश करते थे। UDISE 2019-20 के अनुसार, राज्य में लगभग 1,18,000 सरकारी स्कूल थे, जिनमें कक्षा 1 से 12 तक के लगभग 1.08 करोड़ छात्र नामांकित थे। माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-10) पर स्कूल छोड़ने की दर लगभग 17.9% थी - जो राष्ट्रीय औसत 14.1% से काफी अधिक थी। राज्य की साक्षरता दर 69.3% (जनगणना 2011) थी, जिसमें लिंग के आधार पर काफी अंतर था: पुरुषों की साक्षरता दर 78.7% थी, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 59.2% थी।

ASER 2018 के अनुसार, ग्रामीण मध्य प्रदेश में, कक्षा 5 के केवल 44.8% बच्चे ही अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ पाते थे। राज्य में इंटरनेट की पहुँच सीमित थी: NSS के 75वें दौर (2017-18) के अनुसार, मध्य प्रदेश के ग्रामीण परिवारों में से केवल 20-22% परिवारों के पास ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध थी। मंडला, डिंडोरी, झाबुआ और अलीराजपुर जैसे आदिवासी बहुल जिलों में स्मार्टफोन रखने वालों की संख्या और भी कम थी। राज्य 'हमारा घर हमारा विद्यालय' पहल को लागू कर रहा था, जिसका उद्देश्य रेडियो प्रसारण और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से शैक्षिक सहायता प्रदान करना था। यह पहले से मौजूद बुनियादी ढांचा—भले ही सीमित था—लेकिन जब महामारी फैली, तो यह बेहद प्रासंगिक साबित हुआ।

2.3 भारतीय स्कूलों पर COVID-19 के प्रभाव की समय-रेखा

स्कूल सबसे पहले 16 मार्च, 2020 को बंद किए गए थे, जो राष्ट्रीय लॉकडाउन से कुछ ही दिन पहले की बात है। शुरू में यह उम्मीद थी कि स्कूल कुछ हफ्तों के लिए ही बंद रहेंगे, लेकिन यह बंदी पूरे शैक्षणिक सत्र 2020-21 तक जारी रही। मध्य प्रदेश में, स्कूल मार्च 2020 से लेकर 2021 के ज्यादातर समय तक बंद रहे। राज्य सरकार ने स्कूलों को आंशिक रूप से फिर से खोलने के कई प्रयास किए—जिनमें सितंबर 2020 का एक प्रयास भी शामिल था, जिसे मामलों में अचानक हुई बढ़ोतरी के कारण वापस लेना पड़ा—और आखिरकार नवंबर 2021 से कुछ जिलों में स्कूल फिर से खुल पाए।

3. अनुसंधान क्रियाविधि

यह पेपर एक व्यवस्थित समीक्षा दृष्टिकोण अपनाता है। समीक्षा प्रक्रिया में ये चरण शामिल थे: (a) Google Scholar, PubMed, JSTOR, और सरकारी पोर्टलों सहित विभिन्न डेटाबेस के माध्यम से प्रासंगिक साहित्य की पहचान करना; (b) भारत और मध्य प्रदेश में COVID-19 के शैक्षिक प्रभाव से प्रासंगिकता के आधार पर अध्ययनों की स्क्रीनिंग करना; और (c) चयनित स्रोतों से डेटा निकालना। शामिल करने के मानदंडों के अनुसार, अध्ययन या रिपोर्ट दिसंबर 2021 से पहले प्रकाशित होनी चाहिए और स्कूली छात्रों (कक्षा 1-12) से संबंधित होनी चाहिए। महामारी के संदर्भ की नवीनता को देखते हुए, सरकारी रिपोर्ट, ASER सर्वेक्षण, UDISE डेटा, NCERT सर्वेक्षण और मीडिया-आधारित सर्वेक्षणों सहित 'ग्रे साहित्य' (Grey literature) को भी इसमें शामिल किया गया। यह समीक्षा मार्च 2020 से दिसंबर 2021 तक की अवधि को कवर करती है और इसे विषयगत रूप से पाँच प्रभाव क्षेत्रों में व्यवस्थित किया गया है: सीखने में कमी (learning loss), मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल पहुँच, स्कूल छोड़ने की दरें (dropout rates), और पोषण। जहाँ मध्य प्रदेश (MP) से संबंधित विशिष्ट डेटा उपलब्ध था, उसे अलग से प्रस्तुत किया गया है; अन्यथा, राष्ट्रीय डेटा को मध्य प्रदेश के आधारभूत संकेतकों के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।

4. स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों पर COVID-19 और लॉकडाउन का प्रभाव

4.1 सीखने में कमी और शैक्षिक पिछड़ापन

शायद COVID-19 के कारण स्कूलों के बंद होने का सबसे ज्यादा दर्ज किया गया नतीजा 'सीखने का नुकसान' (learning loss) है - यानी ज्ञान और कौशल में वह गिरावट या ठहराव, जिसका अनुभव छात्र तब करते हैं जब उनकी औपचारिक स्कूली शिक्षा में रुकावट आती है। भारत में, महामारी के कारण स्कूलों के बंद होने का सिलसिला - जो कई राज्यों में 18 महीने या उससे भी ज्यादा समय तक चला - एक ऐसी स्थिति में बदल गया, जिसे शिक्षा विशेषज्ञों ने 'सीखने की आपात स्थिति' (learning emergency) बताया है। ASER सेंटर ने 2020 में 26 राज्यों में फ़ोन के ज़रिए एक तेज़ी से किया जाने वाला सर्वे किया। इसके नतीजे चौंकाने वाले थे: ग्रामीण भारत में, कक्षा 1 से 8 तक के जिन बच्चों का सर्वे किया गया, उनमें से सिर्फ़ 55% बच्चों को ही आम दिनों में सीखने से जुड़ी गतिविधियों तक पहुँच मिल पाई। खास तौर पर मध्य प्रदेश में, यह अनुपात और भी कम था - लगभग 43% - जिसका मुख्य कारण स्मार्टफ़ोन तक सीमित पहुँच और माता-पिता का डिजिटल माध्यम से सीखने में बच्चों की मदद न कर पाना था। निचली कक्षाओं (कक्षा 1 से 3)

के बच्चे - जो बुनियादी साक्षरता और अंकगणित के विकास के सबसे अहम पड़ाव पर होते हैं - इस स्थिति से सबसे ज्यादा प्रभावित पाए गए।

अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी (2021) के एक सर्वे में, जिसमें MP समेत पाँच राज्यों के 1,137 स्कूलों को शामिल किया गया था, यह पाया गया कि 92% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पिछले साल के मुकाबले कम से कम एक खास भाषा की क्षमता खो दी थी और 82% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने गणित की क्षमता खो दी थी। सर्वे में यह भी पाया गया कि कम इनकम वाले परिवारों के स्टूडेंट्स में सीखने का नुकसान (learning loss) काफी ज्यादा था। MP में, मंडला और डिंडोरी जैसे आदिवासी ज़िलों के सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स ने पढ़ने और गणित की क्षमताओं में सबसे ज्यादा गिरावट की जानकारी दी।

तालिका 1: COVID-19 (2020-21) के दौरान मध्य प्रदेश में अनुमानित सीखने की हानि और प्रमुख संकेतक

संकेतक	महामारी से पहले (2018-19)	महामारी के दौरान (2020-21)	स्रोत / टिप्पणी
सीखने की गतिविधियों तक पहुँच वाले बच्चों का % (ग्रामीण MP)	~78% (स्कूल-आधारित)	~43%	ASER सर्वे 2020
कक्षा 2 का पाठ पढ़ने वाले कक्षा 5 के छात्रों का % (ग्रामीण MP)	44.8%	~28-32% (अनुमानित)	ASER 2018; Azim Premji 2021
स्कूल छोड़ने की दर (कक्षा 9-10, MP)	17.9%	अनुमानित 20-25% (प्रक्षेपित)	UDISE 2019-20; SRI 2021
मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चे (MP)	~7.2 मिलियन	स्थगित / आंशिक DBT	GoI MoE 2020; MP सरकार
स्मार्टफ़ोन तक पहुँच वाले बच्चे (ग्रामीण MP)	~22%	~22% (कोई बदलाव नहीं)	NSS 75वाँ दौर 2017-18

स्रोत: ASER 2018, ASER फ़ोन सर्वेक्षण 2020, UDISE 2019-20, अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय 2021, NSS 75वाँ दौर से संकलित।

स्कूल बंद होने से बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान (FLN) के लक्ष्य भी बाधित हुए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का मुख्य हिस्सा थे; इस नीति ने 2025 तक तीसरी क्लास तक के सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल करने का लक्ष्य रखा था। महामारी ने इस लक्ष्य की दिशा में हुई प्रगति को असल में कई साल पीछे धकेल दिया।

4.2 मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

महामारी और उसके साथ लगे लॉकडाउन की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों की मानसिक सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा। घरों में बंद रहना, दोस्तों से अचानक कट जाना, महामारी से जुड़ी खबरें देखकर होने वाली घबराहट, माता-पिता का तनाव और पढ़ाई को लेकर अनिश्चितता—इन सबने मिलकर भारत की युवा आबादी में मानसिक सेहत का एक संकट खड़ा कर दिया। यह संकट ज्यादातर दिविभाजन नहीं दिया, क्योंकि बच्चों और किशोरों की मानसिक सेहत के लिए ज़रूरी ढांचा पहले से ही अपर्याप्त था।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज (NIMHANS) द्वारा 2020 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि शहरी भारत में 10-17 साल के बच्चों में घबराहट, डिप्रेशन और तनाव से जुड़े लक्षणों का स्तर बढ़ा हुआ था। मध्य प्रदेश जैसे ग्रामीण इलाकों में, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की गुणात्मक रिपोर्टों से पता चला कि मानसिक परेशानी के लक्षण बड़े पैमाने पर मौजूद थे; इनमें नींद में दिक्कत, भावनाओं पर काबू न रख पाना और छोटे बच्चों में पीछे की ओर जाने वाला व्यवहार (regressive behaviour) शामिल था। ये निष्कर्ष भारत में बच्चों और किशोरों के लिए मानसिक सेहत से जुड़े ज्यादा समर्थन की तत्काल ज़रूरत को रेखांकित करते हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहाँ संसाधनों तक पहुँच सीमित है। सही समय पर हस्तक्षेप के बिना, मानसिक सेहत से जुड़ी इन समस्याओं के युवा व्यक्तियों की भलाई और विकास पर लंबे समय तक चलने वाले बुरे परिणाम हो सकते हैं। यह बेहद ज़रूरी है

कि सरकार और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता मानसिक सेहत सेवाओं को प्राथमिकता दें और बढ़ते मानसिक सेहत संकट से निपटने के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाएं जो ज़्यादा सुलभ हों और हमारी संस्कृति के अनुरूप हों।

मध्य प्रदेश में किशोरियों पर इसका असर बाकी लोगों के मुकाबले कहीं ज़्यादा पड़ा। स्कूलों के बंद होने से - जो उनके लिए एक सुरक्षित सामाजिक जगह का काम करते थे - उन्हें घरेलू हिंसा, बाल विवाह के दबाव और घर के कामों के बोझ का ज़्यादा सामना करना पड़ा। UNICEF India की 2021 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में लड़कियों पर कम उम्र में शादी का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि स्कूलों के बंद होने से इस कुप्रथा को रोकने वाली एक अहम संस्थागत रुकावट हट गई थी। रिपोर्ट का अनुमान है कि COVID-19 की वजह से अगले दस सालों में दुनिया भर में 1 करोड़ और लड़कियों की कम उम्र में शादी हो सकती है, जिसमें भारत का हिस्सा काफी बड़ा होगा।

मध्य प्रदेश के बालाघाट, सिवनी, मंडला, उमरिया और डिंडोरी जैसे ज़िलों में आदिवासी समुदायों के छात्रों ने गहरे सामाजिक अकेलेपन की भी शिकायत की। स्कूलों के न होने से - जो हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए सामाजिक जुड़ाव का एक ज़रिया भी थे - उनमें अलगाव और निराशा की भावना और बढ़ गई; खासकर ST और SC समुदायों के उन छात्रों में, जो अपने परिवारों में औपचारिक शिक्षा पाने वाली पहली पीढ़ी थे। यह इस बात पर ज़ोर देता है कि शिक्षण संस्थानों और नीति बनाने वालों को न सिर्फ़ छात्रों की पढ़ाई-लिखिभाजन की उपलब्धियों पर, बल्कि उनकी पूरी भलाई पर भी ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है - खासकर उन छात्रों पर जो हाशिए पर पड़े समुदायों से आते हैं। इन कमज़ोर तबकों की मानसिक सेहत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहायता सेवाएँ देना, मेंटरशिप प्रोग्राम चलाना और छात्रों के लिए अपनी भावनाओं को ज़ाहिर करने और मदद मांगने के लिए सुरक्षित जगहें बनाना बहुत ज़रूरी कदम हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदायों के छात्रों की मानसिक सेहत को सहारा देने के लिए एक समग्र नज़रिया अपनाने में स्कूलों, मानसिक सेहत के विशेषज्ञों और सामुदायिक संगठनों के बीच तालमेल बहुत ज़रूरी है।

भारत ने ऐतिहासिक रूप से स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में कम निवेश किया है। प्रशिक्षित स्कूल काउंसलरों की कमी है; अनुशासित अनुपात 250 छात्रों पर 1 काउंसलर का है, लेकिन MP के ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में कोई काउंसलर नहीं है। इसलिए, महामारी ने मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक खालीपन पैदा कर दिया, जिसे दूर करने के लिए कोई संस्थागत व्यवस्था मौजूद नहीं थी।

4.3 डिजिटल विभाजन और ऑनलाइन शिक्षा की विफलताएँ

भारत सरकार का ऑनलाइन शिक्षा की ओर रुख कुछ मान्यताओं पर आधारित था - मुख्य रूप से, डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता और भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्टिविटी - जो मध्य प्रदेश और व्यापक रूप से ग्रामीण भारत के अधिकांश स्कूली छात्रों के लिए सही साबित नहीं हुई।

NSS के 75वें दौर (2017-18) के अनुसार, केवल 24% भारतीय परिवारों के पास किसी भी प्रकार का कंप्यूटर या लैपटॉप था, और केवल 42% परिवारों के पास इंटरनेट की सुविधा थी। ग्रामीण परिवारों में, ये आंकड़े घटकर क्रमशः 14.9% और 24.3% रह गए। मध्य प्रदेश में, ग्रामीण इंटरनेट की पहुंच लगभग 20-22% थी, जो भारत के प्रमुख राज्यों में सबसे कम दरों में से एक थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्मार्टफोन की उपलब्धता - जो ऑनलाइन सीखने का मुख्य माध्यम बन गया था - घर के वयस्क पुरुष सदस्यों तक ही सीमित थी, और छात्रों को अक्सर इसके इस्तेमाल के लिए अपने माता-पिता से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी।

स्कूल बंद होने के जवाब में सरकार ने कई डिजिटल शिक्षण पहलें शुरू कीं, जिनमें DIKSHA (ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर), दूरदर्शन के 'स्वयं प्रभा' शैक्षिक चैनल, और 'PM eVidya' पहल शामिल हैं। मध्य प्रदेश में, राज्य सरकार ने दूरदराज के इलाकों में छात्रों तक पहुंचने के लिए 'डिजिटल शिक्षा' पोर्टल और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के माध्यम से रेडियो-आधारित प्रसारण शुरू किए।

हालाँकि, इन पहलों का असर कई ढाँचागत रुकावटों की वजह से सीमित रहा। MP के कई आदिवासी गाँवों में बिजली की सप्लाई रुक-रुककर होती थी, जिससे डिवाइस-आधारित पढ़ाई करना मुमकिन नहीं हो पाया। DIKSHA पर मौजूद ज़्यादातर कंटेंट हिंदी में था, जिससे गोंडी, कोरकू और भीली जैसी आदिवासी बोलियाँ बोलने वाले समुदायों के छात्रों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। MP के ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों के शिक्षक अक्सर डिजिटल पढ़ाई के तरीकों से अनजान थे और उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, जो उन्हें समय पर नहीं दी गई।

2021 में 'पीपल्स आर्काइव ऑफ़ रूरल इंडिया' (PARI) द्वारा किए गए एक सर्वे में, जिसमें MP के

तालिका 2: डिजिटल पहुँच संकेतक - भारत बनाम मध्य प्रदेश (महामारी-पूर्व, 2017-18)

संकेतक	भारत (ग्रामीण)	मध्य प्रदेश (ग्रामीण)
घरों में इंटरनेट की सुविधा	24.3%	~20-22%
जिन घरों में कंप्यूटर/लैपटॉप है	14.9%	~10-13%
जिन घरों में TV है	~67%	~58-62%
जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन है	~36%	~28-32%
बिजली की सुविधा (ग्रामीण घर)	~89%	~82% (स्थिर आपूर्ति कम है)

स्रोत: NSS 75 वां दौर 2017-18; TRAI 2020; MP आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20; NFHS-5 2019-21

मंडला और झाबुआ जिलों के आदिवासी गाँवों को शामिल किया गया था, ऐसे मामले सामने आए जहाँ पूरे-पूरे गाँवों में एक भी स्मार्टफोन काम नहीं कर रहा था और बच्चे एक साल से भी ज्यादा समय तक किसी भी तरह की व्यवस्थित पढ़ाई से पूरी तरह से कटे हुए थे। सर्वे में पाया गया कि कुछ इलाकों में स्कूल बंद होने के 12 महीनों के अंदर ही 8-12 साल के बच्चे अक्षर और बुनियादी अंकों की पहचान लगभग भूल चुके थे।

4.4 स्कूल छोड़ने की दरें, बाल श्रम और बाल विवाह

महामारी ने लाखों छात्रों के लिए, खासकर सेकेंडरी लेवल पर, हमेशा के लिए स्कूल छोड़ने का खतरा काफी बढ़ा दिया। लॉकडाउन की वजह से रोज़ी-रोटी छिन जाने से पैदा हुई आर्थिक तंगी ने कई परिवारों को - जो पहले से ही गरीबी में जी रहे थे - मजबूर कर दिया कि वे अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लें और उन्हें पैसे कमाने वाले कामों में लगा दें।

मध्य प्रदेश में, 'सेव द चिल्ड्रन' संस्था (2021) ने सागर, जबलपुर ग्रामीण, टीकमगढ़ और छतरपुर जैसे जिलों में ईट भट्टों, खेती-बाड़ी और घरेलू कामों में बाल मज़दूरी में भारी बढ़ोतरी दर्ज की। 12-16 साल के लड़कों पर खेती और कंस्ट्रक्शन के काम में लग जाने का खतरा खास तौर पर ज्यादा था, क्योंकि बड़े पुरुषों के लिए रोज़गार के मौके कम हो गए थे।

लड़कियों के लिए, यह खतरा एक अलग रूप में सामने आया: कम उम्र में शादी के दबाव में भारी बढ़ोतरी। स्कूल बंद होने और परिवारों पर आर्थिक बोझ पड़ने से, बेटियों को धीरे-धीरे एक आर्थिक बोझ के तौर पर देखा जाने लगा। मध्य प्रदेश में काम करने वाले मानवाधिकार संगठनों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बाल विवाह के मामलों में तेज़ी आई; राज्य की 'चाइल्डलाइन' हेल्पलाइन ने अप्रैल से जून 2020 के बीच बाल विवाह से जुड़ी कॉल्स में 17% की बढ़ोतरी दर्ज की, जबकि 2019 में इसी समय के दौरान यह आंकड़ा कम था।

मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले—जिनमें अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और डिंडोरी शामिल हैं—जहाँ पहले से ही आदिवासियों की आबादी बहुत ज्यादा थी और जहाँ ऐतिहासिक रूप से सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने की दर कम रही है, उन्हें खास तौर पर 'बहुत ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्र' के तौर पर पहचाना गया। इन जिलों की लड़कियाँ—खास तौर पर वे लड़कियाँ जो अपने परिवार में पहली बार 9वीं या 10वीं क्लास तक पहुँची थीं—उनके हमेशा के लिए स्कूल छोड़ देने का जोखिम बाकी लड़कियों के मुकाबले कहीं ज्यादा था।

स्कूल के एक सुरक्षित माहौल के तौर पर खत्म हो जाने के नुकसान को कम करके नहीं आँका जा सकता। स्कूल पढ़ाई-लिविभाजन के अलावा भी कई तरह से सुरक्षा का काम करते हैं: वे रोज़ाना का एक तय रूटीन देते हैं, साथियों के साथ घुलने-मिलने का मौका देते हैं, पोषण तक पहुँच सुनिश्चित करते हैं, और वे ऐसी जगहें हैं जहाँ प्रशिक्षित शिक्षक किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या शोषण के संकेतों को पहचानकर उनकी रिपोर्ट कर सकते हैं। स्कूलों के बंद हो जाने से, सबसे ज्यादा कमज़ोर बच्चों के लिए सुरक्षा और निगरानी का यह पूरा तंत्र ही खत्म हो गया।

4.5 पोषण पर प्रभाव: मध्याह्न भोजन योजना में व्यवधान

मिड-डे मील (MDM) योजना, जो दुनिया के सबसे बड़े स्कूल फ्रीडिंग प्रोग्राम में से एक है, मार्च 2020 में स्कूलों के बंद होने पर रोक दी गई थी। मध्य प्रदेश में, महामारी से पहले यह योजना 1,18,000 सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में लगभग 72 लाख

छात्रों को भोजन उपलब्ध कराती थी। इन छात्रों के एक बड़े हिस्से के लिए - खासकर आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए - स्कूल का यह भोजन दिन का सबसे पौष्टिक और कभी-कभी एकमात्र संतुलित भोजन होता था।

देशव्यापी लॉकडाउन के बाद, केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे या तो सूखा राशन बांटें या लाभार्थियों के खातों में खाद्य सुरक्षा भत्ता ट्रांसफर करें। हालाँकि, मध्य प्रदेश में इसका क्रियान्वयन एक जैसा नहीं रहा। 'राइट टू फूड कैंपेन' की 2020 की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि मध्य प्रदेश के कई आदिवासी गाँवों में परिवारों को मिड-डे मील न मिलने के बदले कोई मुआवज़ा नहीं मिला। इस भोजन के न मिलने से स्कूल में बच्चों की उपस्थिति के लिए मिलने वाला एक बड़ा प्रोत्साहन भी खत्म हो गया।

2021 में जारी किए गए मध्य प्रदेश के 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण' (NFHS-5, 2019-21) के आँकड़ों से पता चला कि मध्य प्रदेश में 5 साल से कम उम्र के 41.9% बच्चे 'स्टंटेड' (उम्र के हिसाब से कम कद वाले), 25.8% बच्चे 'वेस्टेड' (वजन में कमी वाले) और 33.6% बच्चे 'अंडरवेट' (कम वजन वाले) थे। ये सभी संकेतक पोषण संबंधी कमज़ोरी की एक गंभीर स्थिति को दर्शाते हैं, जिसे MDM योजना के निलंबन ने और भी ज़्यादा बढ़ा दिया।

5. 2021 में जारी किए गए मध्य प्रदेश के 'राष्ट्रीय परिवार

COVID-19 महामारी ने सभी छात्रों को एक समान रूप से प्रभावित नहीं किया; बल्कि, इसने पहले से मौजूद सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को और बढ़ा दिया। सबसे कमज़ोर समूहों - लड़कियाँ, SC और ST समुदायों के छात्र, दिव्यांग छात्र, और प्रवासी परिवारों के छात्र - को शिक्षा में सबसे गंभीर रुकावटों का सामना करना पड़ा।

लिंग-आधारित विश्लेषण से पता चलता है कि इसका प्रभाव बहुत अलग-अलग रहा। स्कूल बंद होने के कारण, मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में लड़कियों से यह उम्मीद की जाने लगी कि वे घर की ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ उठाएँगी, जिनमें बच्चों की देखभाल, खाना बनाना और घर के अन्य काम शामिल थे। इसके चलते, लड़कों की तुलना में उनके पास खुद से पढ़ाई करने के लिए बहुत कम समय और जगह बचती थी। परिवार का एकमात्र स्मार्टफोन भी लड़कों और घर के बड़े पुरुषों को ज़्यादा आसानी से उपलब्ध हो जाता था।

मध्य प्रदेश के आदिवासी छात्रों को कई तरह की मिली-जुली मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके माता-पिता में से कई लोग मौसमी प्रवासी मज़दूर थे, जो लॉकडाउन के दौरान अपने गाँवों को लौट आए थे, जिससे उन पर आर्थिक बोझ और बढ़ गया। आदिवासी समुदायों के भौगोलिक रूप से अलग-थलग होने के कारण - मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में कई बस्तियों तक गाड़ियों के आने-जाने लायक सड़कें भी नहीं हैं - वहाँ रेडियो सिग्नल भी ठीक से नहीं आते थे। डिजिटल या खुद से पढ़ाई करने के लिए ज़रूरी 'सांस्कृतिक पूंजी' (cultural capital) अक्सर उन परिवारों में मौजूद नहीं होती थी, जहाँ बच्चे पहली बार स्कूल जा रहे थे।

दिव्यांग छात्रों (PWD) को शायद सबसे गंभीर रूप से अलग-थलग किया गया। 'समग्र शिक्षा अभियान' ने मध्य प्रदेश भर के समावेशी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों का नामांकन कराने में काफ़ी प्रगति की थी। ऑनलाइन पढ़ाई की ओर बदलाव, दृष्टि-बाधित, श्रवण-बाधित और बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए लगभग पूरी तरह से पहुँच से बाहर था; जिससे समावेश की दिशा में वर्षों से हुई प्रगति असल में उल्टी पड़ गई।

6. सरकारी नीतिगत प्रतिक्रिया और पहल

6.1 केंद्र सरकार की पहल

केंद्र सरकार ने कई नीतिगत उपायों के ज़रिए शिक्षा के क्षेत्र में आए संकट का सामना किया। मई 2020 में 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज के हिस्से के तौर पर शुरू की गई 'PM eVidya' पहल के तहत, 'एक क्लास, एक चैनल' मॉडल के अंतर्गत हर क्लास (कक्षा 1 से 12 तक) के लिए खास TV चैनल बनाए गए। DIKSHA का विस्तार किया गया ताकि यह सभी राज्यों में शिक्षकों के प्रशिक्षण और छात्रों की पढ़ाई के लिए एक साझा डिजिटल मंच के तौर पर काम कर सके। NCERT ने वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर तैयार किए, ताकि महामारी के दौरान पाठ्यक्रम को प्राथमिकता देने के मामले में शिक्षकों का मार्गदर्शन किया जा सके।

6.2 मध्य प्रदेश राज्य सरकार की पहल

मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने स्थिति के हिसाब से कई खास पहलें शुरू कीं। 'हमारा घर हमारा विद्यालय' (हमारा घर, हमारा स्कूल) कार्यक्रम, जिसे जून 2020 में औपचारिक रूप दिया गया, ने घर पर ही स्कूल का रोज़ाना का शेड्यूल तय किया। इसमें शिक्षकों द्वारा परिवारों को फ़ोन करना, दूरदर्शन MP के ज़रिए पढ़ाई का प्रसारण और समुदाय-स्तर पर शिक्षकों का घर-घर जाकर मिलना शामिल था। इस कार्यक्रम का मकसद स्कूल बंद होने के दौरान भी छात्रों के लिए पढ़ाई का एक नियमित सिलसिला बनाए रखना था।

राज्य सरकार ने 2020-21 में सीखने के स्तर का शुरुआती अंदाज़ा लगाने के लिए अपनी 'प्रतिभा पर्व' मूल्यांकन प्रणाली को दूर से ही लागू किया। हालाँकि, शिक्षकों ने इस दूरस्थ मूल्यांकन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, क्योंकि इसे लागू करने के लिए एक जैसे मानक हालात मौजूद नहीं थे। इसके अलावा, MP सरकार ने 'डिजिटल शिक्षा योजना' भी शुरू की, जिसके तहत शिक्षकों को स्मार्टफोन और डेटा की सुविधा दी गई। इससे वे छात्रों को फ़ोन पर पढ़ा सके और WhatsApp ग्रुप के ज़रिए पढ़ाई का सामान साझा कर सके।

इन सराहनीय प्रयासों के बावजूद, इन पहलों की अपनी कुछ बड़ी सीमाएँ थीं। ASER के फ़ोन सर्वे से पता चला कि MP में लॉकडाउन के दौरान जिन छात्रों का अपने शिक्षकों से किसी भी तरह का संपर्क हो पाया, उनका अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। छात्रों तक पहुँचने का यह सारा बोझ उन सरकारी स्कूल शिक्षकों पर ही ज़्यादा पड़ा, जिन्हें पहले से ही कम वेतन मिलता था। इनमें से कई शिक्षक तो उसी समय COVID-19 को फैलने से रोकने वाली ड्यूटी में भी लगे हुए थे।

7. समीक्षा के मुख्य निष्कर्ष

उपलब्ध साहित्य और डेटा की समीक्षा से ये मुख्य निष्कर्ष सामने आए हैं:

- भारत में COVID-19 के कारण स्कूल 18 महीने से ज़्यादा समय तक बंद रहे, जिससे भारत दुनिया के उन देशों में से एक बन गया जहाँ महामारी के कारण स्कूल सबसे लंबे समय तक बंद रहे।
- मध्य प्रदेश में, ऑनलाइन शिक्षा की ओर बदलाव में सीमित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भारी रुकावट आई; ग्रामीण परिवारों में से 22% से भी कम परिवारों के पास इंटरनेट की सुविधा थी - जिसका नतीजा यह हुआ कि ज़्यादातर छात्र बिना किसी व्यवस्थित पढ़ाई के रह गए।
- पढ़ाई का नुकसान बड़े पैमाने पर और गंभीर था, खासकर निचली प्राइमरी कक्षाओं के छात्रों और वंचित समुदायों के छात्रों के लिए; अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन के अनुमानों के अनुसार, 92% से ज़्यादा छात्रों में पढ़ाई के स्तर में गिरावट देखी गई।
- महामारी का स्कूली बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर पड़ा है, लेकिन मध्य प्रदेश में स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग न होने के कारण इस समस्या पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया।
- स्कूल छोड़ने का खतरा काफी बढ़ गया; मध्य प्रदेश के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों की लड़कियों को कम उम्र में शादी और घर के कामों में लगा दिए जाने, इन दोहरे खतरों का सामना करना पड़ा।
- मिड-डे मील योजना के बंद होने से मध्य प्रदेश के 72 लाख से ज़्यादा बच्चों से पोषण का एक अहम सहारा छिन गया, जिससे पहले से मौजूद पोषण संबंधी कमज़ोरियाँ और भी बढ़ गईं।
- अनुसूचित जनजाति समुदायों के छात्रों, लड़कियों, अपने परिवार में पहली बार स्कूल जाने वाले बच्चों, दिव्यांग बच्चों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को पढ़ाई में सबसे ज़्यादा रुकावटों का सामना करना पड़ा।
- 'हमारा घर हमारा विद्यालय' और 'PM eVidya' जैसी सरकारी पहलें अच्छे कदम थे, लेकिन वे सबसे ज़्यादा वंचित छात्रों तक पहुँचने और उन्हें पढ़ाई से जोड़ने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए।

8. सुधार के लिए सुझाव

साक्ष्यों की समीक्षा के आधार पर, निम्नलिखित नीतिगत और कार्यक्रम-संबंधी अनुशंसाएँ प्रस्तावित की जाती हैं:

8.1 मध्य प्रदेश राज्य सरकार की पहल

मध्य प्रदेश और पूरे भारत के स्कूलों को फिर से खुलने के दौरान, सीखने में हुए नुकसान का पता लगाने और उसे दूर करने के लिए, व्यवस्थित 'ब्रिज' लर्निंग प्रोग्राम शुरू करने चाहिए। इन प्रोग्राम में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए बुनियादी साक्षरता और अंकज्ञान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और इन्हें स्थानीय भाषाओं—जिनमें आदिवासी भाषाएँ भी शामिल हैं—के हिसाब से ढाला जाना चाहिए। 'निपुण भारत' पहल (2021) एक राष्ट्रीय ढाँचा प्रदान करती है, जिसे मध्य प्रदेश में पूरी तत्परता और पर्याप्त संसाधनों के आवंटन के साथ लागू किया जाना चाहिए।

8.2 विद्यालय-आधारित मानसिक स्वास्थ्य सहायता

हर स्कूल क्लस्टर में एक प्रशिक्षित काउंसलर या मानसिक स्वास्थ्य सहायता तंत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कम से कम, शिक्षकों को छात्रों में भावनात्मक परेशानी के लक्षणों को पहचानने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए विशेष पेशेवर प्रशिक्षण मिलना चाहिए। राज्य को बड़े पैमाने पर यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए NGOs और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ साझेदारी करनी चाहिए।

8.3 डिजिटल विभाजन को कम करना

महामारी ने यह बात बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने ला दी है कि 'डिजिटल डिवाइड' (डिजिटल विभाजन) शिक्षा में समानता का एक गंभीर संकट है। मध्य प्रदेश के आदिवासी और दूरदराज के इलाकों में कम लागत वाले, समुदाय-आधारित लर्निंग डिवाइस उपलब्ध कराने और बुनियादी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्य सरकार को स्थानीय और आदिवासी भाषाओं में सामुदायिक रेडियो और टीवी-आधारित शैक्षिक सामग्री को मज़बूत बनाने में भी निवेश करना चाहिए।

8.4 पढ़ाई छोड़ने से रोकना और पुनः नामांकन

मध्य प्रदेश के हर स्कूल को एक घरेलू-स्तर का सर्वे करना चाहिए, ताकि उन छात्रों की पहचान की जा सके जिन्होंने महामारी के दौरान पढ़ाई छोड़ दी थी। लक्षित पुनः-नामांकन अभियान चलाए जाने चाहिए, जिनमें विशेष रूप से आदिवासी ज़िलों की लड़कियों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। बाल श्रम और बाल विवाह के आर्थिक प्रलोभनों को कम करने के लिए, सशर्त नकद हस्तांतरण योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को मज़बूत किया जाना चाहिए।

8.5 मध्याह्न भोजन योजना की बहाली

स्कूलों के फिर से खुलने पर मिड-डे मील योजना को तुरंत पूरी तरह से चालू किया जाना चाहिए, और इसमें पोषण के मानकों को और बेहतर बनाया जाना चाहिए—खास तौर पर उन ज़िलों में जहाँ बच्चों के विकास में रुकावट (stunting) और कमज़ोरी (wasting) की दर ज़्यादा है। महामारी के बाद की रिकवरी की योजना बनाते समय, इस योजना की भूमिका को स्कूल में बच्चों की हाज़िरी बढ़ाने के एक प्रोत्साहन के तौर पर और भूख से बचाने वाले एक सुरक्षा कवच के तौर पर ज़रूर पहचाना जाना चाहिए।

8.6 लिंग-संवेदनशील और समावेशी दृष्टिकोण

मध्य प्रदेश में शिक्षा सुधार के सभी कार्यक्रमों में लिंग-संवेदनशील घटकों को शामिल किया जाना चाहिए। इनमें लड़कियों की घरेलू ज़िम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई का लचीला समय, दूरदराज के इलाकों में लड़कियों के लिए सुरक्षित परिवहन या छात्रावास की सुविधाएँ, और बाल विवाह के खिलाफ तथा लड़कियों की शिक्षा जारी रखने के समर्थन में सामुदायिक स्तर पर जागरूकता अभियान शामिल हैं।

9. निष्कर्ष

COVID-19 महामारी और इसके कारण ज़रूरी हुए लॉकडाउन ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक संकट खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश में, यह संकट महामारी से पैदा हुई आम रुकावटों और राज्य की पहले से मौजूद शैक्षिक कमज़ोरियों, सीमित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीबी की उच्च दरें, लैंगिक असमानताएँ, और आदिवासी तथा ग्रामीण समुदायों को शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नुकसान के मेल से बना है।

इस समीक्षा में सीखने के नतीजों, मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल पहुँच, पढ़ाई छोड़ने के जोखिम और पोषण पर महामारी के बहुआयामी असर को दर्ज किया गया है। सबूत लगातार यह दिखाते हैं कि सबसे ज़्यादा हाशिए पर मौजूद छात्रों को ही सबसे ज़्यादा बोझ उठाना पड़ा। लॉकडाउन ने मध्य प्रदेश में शैक्षिक असमानता पैदा नहीं की, बल्कि इसने उस असमानता को उजागर किया और गहरा कर दिया जो पहले से ही मौजूद थी।

मध्य प्रदेश में शिक्षा की बहाली का रास्ता न तो आसान है और न ही सस्ता। इसके लिए लगातार राजनीतिक इच्छाशक्ति, पर्याप्त फंडिंग, ज़मीनी स्तर पर लागू करने की क्षमता, और सबसे ज़रूरी बात, एक मार्गदर्शक सिद्धांत के तौर पर समानता के प्रति प्रतिबद्धता की ज़रूरत है। महामारी के शैक्षिक नतीजे खुद महामारी के खत्म होने के बाद भी बने रहेंगे; छात्रों की पूरी एक पीढ़ी को सीखने में जो नुकसान हुआ है, उसके उनके आर्थिक अवसरों और भलाई पर जीवन भर असर पड़ेंगे।

इस समीक्षा का मकसद उन सबूतों के आधार में योगदान देना है, जो महामारी के बाद शिक्षा की बहाली की नीति को दिशा देने के लिए ज़रूरी हैं।

संदर्भ:

- [1] ASER Centre. (2019). Annual Status of Education Report (Rural) 2019. New Delhi: ASER Centre.
- [2] ASER Centre. (2021). ASER 2021: Wave 1 - Young Children (Phone Survey). New Delhi: ASER Centre.
- [3] Azim Premji University. (2021). Loss of Learning During the Pandemic. Bangalore: Azim Premji University.
- [4] Government of India, Ministry of Education. (2020). Annual Report 2019-20. New Delhi: MoE.
- [5] Government of Madhya Pradesh. (2020). Hamara Ghar Hamara Vidyalaya - Programme Guidelines. Bhopal: MP School Education Department.
- [6] Government of Madhya Pradesh. (2020). MP Economic Survey 2019-20. Bhopal: Finance Department, GoMP.
- [7] International Labour Organization (ILO). (2021). COVID-19 and Child Labour: A Time of Crisis, A Time to Act. Geneva: ILO.
- [8] Ministry of Health and Family Welfare. (2021). National Family Health Survey (NFHS-5) 2019-21 - State Fact Sheet: Madhya Pradesh. New Delhi: MoHFW.
- [9] National Council of Educational Research and Training (NCERT). (2021). National Achievement Survey 2021 - State Report: Madhya Pradesh. New Delhi: NCERT.
- [10] National Sample Survey (NSS). (2019). NSS 75th Round: Household Social Consumption - Education (2017-18). New Delhi: Ministry of Statistics & PI.
- [11] NIMHANS. (2020). Mental Health and Well-being of Children During COVID-19. Bangalore: NIMHANS.
- [12] Right to Food Campaign. (2020). Mid-Day Meal and COVID-19: A Status Report. New Delhi: Right to Food Campaign India.
- [13] Sinha, D., & Sarda, A. (2021). Pandemic, Education and Equity: Evidence from Rural India. Economic and Political Weekly, 56(14), 34-41.
- [14] UDISE+. (2020). Unified District Information System for Education Plus 2019-20: State Profile - Madhya Pradesh. New Delhi: MoE.
- [15] UNESCO. (2020). COVID-19 Education Response: How Many Students Are at Risk of Not Returning to School? Paris: UNESCO.
- [16] UNICEF India. (2021). COVID-19 and Girls' Education in South Asia. New Delhi: UNICEF India.
- [17] United Nations. (2020). Policy Brief: Education During COVID-19 and Beyond. New York: UN.
- [18] World Bank. (2020). The COVID-19 Pandemic: Shocks to Education and Policy Responses. Washington D.C.: World Bank.
- [19] World Health Organization (WHO). (2020). WHO Director-General's Opening Remarks at the Media Briefing on COVID-19, 11 March 2020. Geneva: WHO.
- [20] Yadav, S. S., & Pal, P. K. (2021). COVID-19 and Education in Tribal Communities of Central India: A Field Report. Journal of Tribal Studies, 26(2), 88-102.